कृपया प्रकाशनार्थ **5 अक्तूबर 2009**

भाजपा नेता व पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री राम नाईक ने सोमवार, 5 अक्तूबर 2009 को मुंबई में पत्रकार परिषद में जारी किया वक्तव्य

महंगाई से पीडित जनता कांग्रेस को परास्त करेगी - राम नाईक

मुंबई, सोमवार : "केंद्र सरकार से महाराष्ट्र में जनहित के निर्णय करवाने हैं तो महाराष्ट्र की बागडौर भाजपा-शिवसेना युती को ही सौंपनी होगी, यह राय अब जनता ने बनायी है", ऐसा अभिमत पूर्व केंद्रिय मंत्री व भाजपा नेता श्री राम नाईक ने व्यक्त किया. भारतीय जनता पार्टी, मुंबई द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में आयोजित पत्रकार परिषद में श्री नाईक बोल रहे थे.

बढती महंगाई :

इस विधानसभा चुनाव का सबसे अहम् विषय है बढती महंगाई. दीपावली नजदीक आ रही है मगर फिर भी आम आदमी त्यौहार के लिए खरीदारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, यह हकीकत है. इस महंगाई पर नियंत्रण रखने का काम भाजपा-शिवसेना की सरकार ही कर पाएगी. गेंहू, चावल, तेल, शक्कर व तूर दाल के दाम आनेवाले पाँच वर्षों तक स्थिर रखने का युती का वादा है ऐसा बता कर श्री राम नाईक ने पिछले पाँच वर्षों में वाजपेयी सरकार की तुलना में जीवनावश्यक चीजों के दाम बढ कर महंगाई कैसे आसमान छू रही है इसकी जानकारी देनेवाला पत्रक भी पेश किया. इस पत्रक से साफ दिखाई देता है कि पिछले पाँच वर्षों में दामों में प्रति किलो गेंहू रु. 9 से रु. 18 (100 प्रतिशत वृध्दी), चावल रु. 10 से रु. 24 (140 प्रतिशत वृध्दी), शक्कर रु. 14 से रु. 34 (142 प्रतिशत वृध्दी), गूड रु. 14 से रु. 42 (200 प्रतिशत वृध्दी), तूर दाल रु. 30 से रु. 90 (200 प्रतिशत वृध्दी) वृध्दी हुई है. महंगाई के कारण नाराज मतदाता कांगेस - राष्ट्रवादी सरकार को परास्त कर अपना गुस्सा दिखाएगी, ऐसा विश्वास श्री राम नाईक ने जताया.

उपनगरीय रेल :

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों को उनकी दैनंदिन यात्रा में केंद्र सरकार राहत दिलाने का काम कर सकती थी. मगर न केंद्र सरकार को मुंबईवासियों की चिंता है न राज्य सरकार को कुछ पडी है. इस परिस्थिती में भाजपा-शिवसेना सरकार परिवर्तन करेगी ऐसा विश्वास दिला कर श्री राम नाईक ने कहा,"उपनगरीय रेल मुंबईवासियों की जीवनरेखा है. भारी भीड में हर दिन यात्रा करनेवाले 65 लाख यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में कुछ भी नही किया. वाजपेयी सरकारद्वारा मुंबई के लिए शुरु किए प्रकल्पों की गति धीमी कर देने का एकमात्र काम इस सरकार ने किया. वाजपेयी सरकार ने मुंबई रेलवे विकास महामंडल के माध्यम से मुंबई उपनगरी रेल सेवा का स्तर सुधारने के लिए एमयुटीपी I के तहत रु. 4,500 करोड के काम शुरु करवाए. चूँकी मुंबई रेल्वे विकास महामंडल में भारतीय रेल व महाराष्ट्र सरकार का बराबरी का हिस्सा है इन योजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य सरकार को संभव था. किंतु महाराष्ट्र की कांग्रेस आघाडी सरकार ने इन कामों पर थोडा सा भी ध्यान नही

दिया. भाजपा-शिवसेना सरकार मुंबई वासियों के हित को मद्देनजर रखते हुए मुंबई रेल विकास प्राधिकारण की सभी योजनाओं को पुरी करवाएगी. एमयुटीपी - I के साथ ही साथ रु. 5,300 करोड की एमयुटीपी -II की योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी", ऐसा भी श्री राम नाईक ने कहा.

मेट्रो रेल :

मेट्रो रेल योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है ऐसा भी श्री नाईक का मानना है. चूँकी मेट्रो रेल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसकी परियोजनाओं के कारण बेघर होनेवालों के पुनर्वसन की नीती कांग्रेस-राष्ट्रवादी की राज्य सरकार ने अब तक तय नही की इस बात पर श्री नाईक ने नाराजगी जतायी. श्री नाईक ने कहा कि हम पहले पुनर्वसन नीति बनाएंगे और बाद में योजनओं को शीघ्र पुरा करने की कोशिश भी करेंगे. "वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो रेल के काम को प्राथमिकता देंगे. चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द योजना का भूमिपूजन तो राष्ट्रपति महोदया ने किया किंतु वह काम अब तक शुरु क्यों नही हुआ उसकी भी जाँच करेंगे. साथ ही साथ प्रस्तावित चारकोप कारशेड की जगह बदलने के बाद ही हम वह काम शुरु करेंगे", ऐसा भी श्री राम नाईक ने कहा.

वनभूमि :

पश्चिम व पूर्व उपनगरों में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के बाहर कथित वनीभूमि पर लाखो लोग रहते हैं. यहाँ जैसे जुग्गी-झोपडीयां है वैसे ही अपनी पूरी पूँजी लगा कर, सभी नियमों का पालन कर खरीदे फ्लैटों में रहनेवाले भी हजारों परिवार है. इनमें से किसी को भी भाजप-शिवसेना सरकार बेघर नही होने देगी. इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार अपनी भूमिका आग्रह से रखेगी और आवश्यकता पडने पर कानून में सुधार भी करेगी, ऐसा भी श्री नाईक ने कहा.

महानगर गैस :

वाजपेयी सरकार में श्री राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे. तब लाखो परिवारों को महानगर गैस द्वारा सस्ता व अधिक सुरक्षित पाईप गैस दिया गया. महानगर गैस में भी राज्य सरकार की भागीदारी है. संपूर्ण मुंबई में पाईप गैस का जाल फैले इस बात पर राज्य सरकार ने ख्याल करना चाहीए था. विद्यमान पेट्रोलियम मंत्री श्री मुरली देवड़ा मुंबई के ही होने के बावजूद इस काम की गति भी काफी धीमी हो गयी है. सभी को जल्द से जल्द पाईप गैस मिलें और जो लोगों ने दो-दो साल से इसके लिए पैसा भरा है उन्हे 6 महिने के भीतर गैस कनेक्शन मिले इसलिए भाजपा-शिवसेना आग्रह रखेगी ऐसा भी श्री राम नाईक ने स्पष्ट किया.

(विवेकानंद गुप्ता)
प्रसिध्दी प्रमुख
9869233624

संलग्न : महंगाई का पत्रक

जीवनावश्यक वस्तुओं के बढते दाम

(सभी दाम मुंबई के दुकानों के हैं - संकलक श्री.राम नाईक)

वस्तू	**भाजपा शासन में दाम (प्रति किलो रु.) मई 2004**	**कांग्रेस शासन में दाम (प्रति किलो रु) 1 अक्तूबर 2009**	**वृध्दि(प्रति शत)**
गेंहू	9	18	100%
चावल	10	24	140%
शक्कर	14	34	142%
चाय पावडर	80	200	150%
तेल	40 (प्रति लिटर)	88(प्रति लिटर)	120%
डालडा	40	60	50%
तूर दाल	30	90	200%
मूंग दाल	24	68	183%
मसूर दाल	22	68	209%
चना दाल	25	45	80%
गुड़	14	42	200%
बेसन	20	45	125%
आलू	8	20	150%
प्याज	6	20	233%
टमाटर	9	12	33%
दूध	14 (प्रति लिटर)	25(प्रति लिटर)	78%
मिट्टी का तेल	18 (प्रति लिटर)	35(प्रति लिटर)	94%
रसोई गैस	244 (प्रति सिलेंडर)	314.00 (प्रति सिलेंडर)	29%
पाइप नैसर्गिक गॅस	11.53(प्रति एससीएम)	13.60 (प्रति एससीएम)	18%
पेट्रौल	33.15 (प्रति लिटर)	48.78 (प्रति लिटर)	47%
डिजल	22.50 (प्रति लिटर)	36.74 (प्रति लिटर)	63%
सीएनजी	19.71 (प्रति किलो)	24.65(प्रति किलो)	25%

महंगाई आस्मान छू रही है, मगर सरकार बता रही है कि महंगाई सूचकांक कम हो रहा है; इस सप्ताह वह मात्र (-) ०.83 है. सूचकांक घट रहा है क्योंकि ग्राहक मूल्य सूचकांक निकालने की पुरानी पध्दती बंद कर अब सरकार वह थोक मूल्य पर निर्धारीत करती है. इससे देश की अर्थ व्यवस्था का गलत चित्र दिखाया जाता है. महंगाई तो बढ ही रही है, इसलिए तो सरकार ने अपने कर्मचारीयों का महंगाई भत्ता भी बढाया है. महंगाई के साथ-साथ देश पर मंदी का साया भी फैल गया है. यह मुसिबतें क्या कम थी कि अब हमे अकाल का भी सामना करना पडेगा.

कांग्रेस आघाडी सरकार इस संकट काल में भी निष्क्रीय और संवेदनाहीन बनी है. चलो! महंगाई बढानेवाली इस सरकार को हटाना है.